VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(02 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा 'स्मार्ट (SMART)' पुलिसिंग पर बल
- चक्रवात 'फेंगल' का तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रकोप
- संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) में प्लास्टिक प्रदूषण पर कोई समझौता नहीं
- MCQs

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा 'स्मार्ट (SMART)' पुलिसिंग पर बल:

चर्चा में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों (डीजीपी/आईजीपी) के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए देश के पुलिस बलों से 'स्मार्ट पुलिसिंग मंत्र' अपनाने का आह्वान किया, जिसमें 'स्मार्ट (SMART)' का विस्तार करके अब 'रणनीतिक (Strategic), सावधानीपूर्वक (Meticulous), अनुकूलनीय (Adaptable), विश्वसनीय (Reliable) और पारदर्शी (Transparent)' कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उत्पन्न खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बाधित करने के लिए 'डीप फेक' की क्षमता पर चिंता व्यक्त की और पुलिस से भारत की दोहरी एआई शक्ति 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'आकांक्षी भारत (Aspirational India)' का उपयोग करके इस चुनौती को अवसर में बदलने को कहा।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा:

- प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर हुई व्यापक चर्चा और चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिस व्यवस्था में की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कांस्टेबल स्तर के पुलिस बलों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया और सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए।
- उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और नार्को-तस्करी सहित बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा पर उभरती सुरक्षा चिंता शामिल हैं।

भारत की पूर्वी सीमा को लेकर सुरक्षा चिंता:

- भारत की भूमि सीमा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां कट्टरपंथी गतिविधियों के बढ़ने से भारत को वहां हो रहे घटनाक्रम से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के

लिए मजबूर होना पड़ा है। कई एजेंसियों की रिपोर्ट पहले ही संकेत दे चुकी है कि भारत की सुरक्षा के लिए दुश्मन ताकतें बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर में अशांति पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं।

- मणिपुर में मौजूदा अशांति के बाद म्यांमार के मोर्चे पर भी भारत को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को और खराब करने वाली बात यह है कि मणिपुर में मौजूदा अशांति में म्यांमार से संचालित उग्रवादी संगठनों का हाथ पाया गया है।

नक्सलवाद या वामपंथी चरमपंथ (LWE) की चुनौती:

- चूंकि भारत सरकार ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की समयसीमा तय की है, इसलिए इस बैठक में इस खतरे से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने पर भी चर्चा की गयी है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नक्सलवाद के कारण 8 करोड़ से अधिक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
- गौरतलब है कि नक्सलवाद के खिलाफ सक्रिय दृष्टिकोण के कारण वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई है, जो 2004 से

2014 के बीच 16,463 मामलों से घटकर पिछले 10 वर्षों में 7,700 हो गई है। इस साल जनवरी से अब तक कुल 237 नक्सलियों को मार गिराया गया है, 812 को गिरफ्तार किया गया है और 723 ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया है - जो नक्सल हिंसा का गढ़ है।

तटीय सुरक्षा की चुनौती:

- भारत की तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है जो मुख्य भूमि और द्वीपों से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्य और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे चार केंद्र शासित प्रदेश तट पर स्थित हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और खाड़ी देशों से ऐसी तटीय सीमाओं की भौतिक निकटता इसकी भेद्यता को और बढ़ा देती है।
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से समुद्री मार्गों के माध्यम से नशीली दवाओं के साथ-साथ हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी ने भारत की तटीय सुरक्षा की भेद्यता को बढ़ा दिया है।

सीमापार से मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या:

- विदेशी धरती से मादक पदार्थों की तस्करी ने भी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है। मादक पदार्थों के कारोबार में अपराधियों और गैंगस्टरों के साथ-साथ सीमापार के भारत विरोधी राज्य एवं गैर राज्य तत्वों की संलिप्तता ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

साइबर अपराध से जुड़ी गंभीर चुनौती:

- हालांकि केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, लेकिन निवेश घोटाला, पार्ट टाइम जॉब घोटाला, तुरंत लोन, डिजिटल गिरफ़्तारी, डेटिंग घोटाला, रिफंड घोटाला, फ़र्जी गेमिंग ऐप, साइबर गुलामी, सेक्सटॉर्शन समेत अलग-अलग तरह के साइबर अपराध ने देश में स्थिति को और खराब कर दिया है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2024 के पहले नौ महीनों में भारत को साइबर धोखाधड़ी से लगभग 11,333 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) के आंकड़ों से पता चला है कि 2024 में लगभग 12 लाख साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 45% दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- कंबोडिया, म्यांमार

और लाओस से आईं। वर्ष 2021 से, CFCFRMS ने 30.05 लाख शिकायतें दर्ज की हैं, जिससे ₹27,914 करोड़ का नुकसान हुआ है।

आर्थिक तंत्र से जुड़ी सुरक्षा चुनौती:

- नकली मुद्रा का प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इसका उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों को वित्तपोषित करने और देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नकली नोटों का प्रचलन काफी बढ़ गया है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 500 रुपये के नकली नोटों में 317 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2018-19 में 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 21,865 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 91,110 मिलियन हो गई। वित्त वर्ष 2023-24 में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह संख्या 85,711 मिलियन हो गई।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

चक्रवात 'फेंगल' का तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर में प्रकोप:

चर्चा में क्यों है?

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 दिसंबर को बताया कि चक्रवात फेंगल एक धीमी गति से बढ़ने वाला चक्रवात है, जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। IMD के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के एस बालचंद्रन ने कहा, "चक्रवाती तूफान फेंगल अब पुडुचेरी के पास लगभग स्थिर हो गया है और धीरे-धीरे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे-जैसे यह अंतर्देशीय क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, नीचे की जमीन से घर्षण धीरे-धीरे इसके खत्म होने की ओर ले जाएगा। लेकिन इससे पहले, यह जमीन पर बहुत अधिक बारिश करेगा"।
- चक्रवात फेंगल ने पुडुचेरी में पहले ही कहर बरपा दिया है। IMD ने बताया कि 1 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में पुडुचेरी शहर में 48.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह 1995-2024 की अवधि के लिए पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक 24 घंटे की संचयी वर्षा है।

- उल्लेखनीय है कि चक्रवात फेंगल एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) चक्रवातों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

चक्रवात क्या होता है?

- चक्रवात हवा की एक बड़ी प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। यह आमतौर पर विनाशक तूफान और खराब मौसम के साथ होता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली हवाएँ हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं जो मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी तूफान हैं।
- ऐसे चक्रवात तब बनते हैं जब तूफानी गतिविधियां परिसंचरण केंद्र के करीब बनने लगती हैं, तथा सबसे तेज हवाएं और बारिश अब केंद्र से दूर नहीं होती हैं। तूफान का केंद्र गर्म होता रहता है, और चक्रवात को अपनी अधिकांश ऊर्जा उस "गुप्त ऊष्मा" से मिलती है, जो जलवाष्प के द्रव जल में संघनित होने से निकलती है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उनके स्थान और शक्ति के आधार पर अलग-अलग नाम होते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में 'हरिकेन' के रूप में जाना जाता है। वहीं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत में, उन्हें 'टाइफून' कहा जाता है।

अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है?

- एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान प्रणाली है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद क्षैतिज तापमान अंतर से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। यू.एस. नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, उनके केंद्र में "ठंडी हवा होती है, और जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलते हैं, तो संभावित ऊर्जा की रिहाई से उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है"।
- उल्लेखनीय है कि एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात (जिसे मध्य-अक्षांशीय चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है) कम दबाव वाली प्रणाली है जिसमें ठंडे मोर्चे, गर्म मोर्चे और अवरुद्ध मोर्चे जुड़े होते हैं। इसके विपरीत, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आमतौर पर पृथ्वी की सतह पर तूफान के पार तापमान में बहुत कम या कोई अंतर नहीं होता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) में प्लास्टिक प्रदूषण पर कोई समझौता नहीं:

मुद्दा क्या है?

- बुसान में संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की पांचवीं और अंतिम बैठक में वार्ता की अध्यक्षता कर रहे राजनयिकों ने 1 दिसंबर, 2024 को कहा कि वार्ताकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक संधि पर सहमति बनाने में विफल रहे हैं, तथा चर्चा जारी रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गयी है।
- उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह की वार्ता "उच्च-महत्वाकांक्षी" देशों, जो उत्पादन को सीमित करने और हानिकारक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वैश्विक रूप से बाध्यकारी समझौते की मांग कर रहे हैं, और "समान विचारधारा वाले" देश जो कचरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, के बीच गहरे मतभेदों को हल करने में विफल रही है।

प्लास्टिक प्रदूषण पर विभिन्न देशों में मतभेद:

- हालांकि देशों ने सीधे तौर पर उन देशों के नाम बताने से इनकार कर दिया है जो इस समझौते को रोक रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और रूस सहित अधिकांश तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन में कटौती और अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रोकने की कोशिश की है।
- 100 से ज़्यादा देश उत्पादन में कटौती का लक्ष्य तय करने का समर्थन कर रहे हैं और दर्जनों देश कुछ रसायनों और अनावश्यक प्लास्टिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी समर्थन करते हैं।
- दुनिया के दो सबसे बड़े प्लास्टिक उत्पादकों, चीन और अमेरिका की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 1 दिसंबर, 2024 को एक मज़बूत संधि का आग्रह करने वाले देशों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही देश मंच से अनुपस्थित थे।
- प्लास्टिक उद्योग संघ के अनुसार, 2023 में चीन प्लास्टिक उत्पादों का अब तक का सबसे बड़ा निर्यातक था, उसके बाद जर्मनी और अमेरिका का स्थान था। तीनों देशों का कुल वैश्विक प्लास्टिक व्यापार का 33% हिस्सा है।

वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर होती चुनौती:

- 2022 में वैश्विक स्तर पर सालाना प्लास्टिक उत्पादन बढ़कर 40 करोड़ टन से ज्यादा हो गया था। इसमें से करीब 35 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे के रूप वापस आ रहा है।
- विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि 2050 तक 2,600 करोड़ मीट्रिक टन नए प्लास्टिक का उत्पादन हो जायेगा। अफसोस की बात है कि इस प्लास्टिक का करीब आधा कचरे का हिस्सा बन जाएगा।
- 90% से अधिक प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है, जबकि 2060 तक प्लास्टिक उत्पादन तीन गुना बढ़ जाने की उम्मीद है। दुनिया का ज्यादातर प्लास्टिक लैंडफिल में चला जाता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है या जला दिया जाता है।

भारत में प्लास्टिक पर्यावरण की समस्या:

- सितम्बर माह में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का योगदान पांचवें हिस्से के बराबर है।
- भारत हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक जलाता है और 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक को मलबे के रूप में पर्यावरण में छोड़ता है। कुल मिलाकर, भारत सालाना दुनिया में 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देता है, जो

इस सूची में अगले देशों - नाइजीरिया (3.5 मिलियन टन), इंडोनेशिया (3.4 मिलियन टन) और चीन (2.8 मिलियन टन) की तुलना में काफी अधिक है - और पिछले अनुमानों से भी अधिक है।

- इससे पहले, चीन को शीर्ष वैश्विक प्रदूषक के रूप में पहचाना गया था, लेकिन देश चौथे स्थान पर आ गया है।

इस शोध की आलोचना:

- यह अध्ययन, व्यापक होते हुए भी, कुछ उच्च आय वाले देशों से होने वाले उत्सर्जन को कम करके आंक सकता है क्योंकि इसमें प्लास्टिक कचरे के निर्यात को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही यह अध्ययन ऐसे समय में आया है जब प्लास्टिक प्रदूषण पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए संधि वार्ता होने वाली है। और ये जानकारियाँ आगामी वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- उल्लेखनीय है कि एक तरफ जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश और उद्योग समूह हैं, जो प्लास्टिक प्रदूषण को "अपशिष्ट प्रबंधन समस्या" के रूप में देखते हैं, और उत्पादन पर अंकुश लगाने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ और अफ्रीका के देश हैं, जो एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना चाहते हैं और उत्पादन पर अंकुश लगाना चाहते हैं।

अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEP) के पांचवें सत्र में वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया।
- इस प्रस्ताव में अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) को प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने और वैश्विक समझौते के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव में 2024 तक अंतर-सरकारी वार्ता समिति की वार्ता को समाप्त करने की महत्वाकांक्षा रखी गई थी। साल 2022 से अब तक अंतर-सरकारी वार्ता समिति के चार सत्र उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा और केन्या में आयोजित किए जा चुके हैं।
- INC का पांचवां सत्र 25 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक बुसान में आयोजित किया गया, यह अंतर-सरकारी वार्ता समिति का अंतिम नियोजित सत्र है और इसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर वार्ता पूरी होने की उम्मीद थी, जो कि पूरी न हो सकी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. सितम्बर माह में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 'भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. भारत प्लास्टिक प्रदूषण में विश्व में सर्वाधिक योगदान देता है।
   2. यह अध्ययन कुछ उच्च आय वाले देशों से होने वाले प्लास्टिक उत्सर्जन को कम करके आंकता है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans:(c)

2. वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव में, प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए, अंतर-सरकारी वार्ता समिति की वार्ता को कब तक समाप्त करने की महत्वाकांक्षा रखी गई थी?

   (a) 2023 तक

   (b) 2024 तक

   (c) 2026 तक

   (d) 2030 तक

   Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह चक्रवात एक ऐसी तूफान प्रणाली है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद क्षैतिज तापमान अंतर से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है।
2. ये चक्रवात एक उच्च दबाव वाली प्रणाली है जिसमें ठंडे मोर्चे, गर्म मोर्चे और अवरुद्ध मोर्चे जुड़े होते हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)

4. चर्चा में रहे चक्रवात 'फेंगल' को लेकर निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।

(b) यह एक धीमी गति से बढ़ने वाला चक्रवात है।

(c) इसके कारण पुडुचेरी में पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक 24 घंटे की संचयी वर्षा हुई है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans:(d)

5. पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा 'स्मार्ट' पुलिसिंग पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए 'स्मार्ट (SMART)' पुलिसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यहां पर 'स्मार्ट' पुलिसिंग का आशय 'स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचिवेबल, रिलेवेंट और टाइमबॉन्ड' पुलिसिंग से है।
2. यहां पर 'स्मार्ट' पुलिसिंग का आशय 'स्ट्रैटेजिक, मेटिकुलस, अडॉप्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट' पुलिसिंग से है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(b)